ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, सोमवार 22 जुलाई 2024

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 1 अंक 142

NEET के विवादित सवाल की जांच के आदेश : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- IIT दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट पैनल बनाएं; कल 12 बजे तक रिपोर्ट दें

जस्टिस जे बी पारदीवाला | चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ | जस्टिस मनोज मिश्रा

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली. NEET मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजें।

NEET गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई। यह चौथी सुनवाई थी। अगली सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी। इसके अलावा, CJI ने याचिकाकर्ताओं से आज शाम तक आधे पेज में NEET UG रीटेस्ट के पक्ष में तर्क का रिटन सबमिशन ई-मेल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान NTA ने माना कि 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया था। इन्हें SBI की जगह केनरा बैंक का पेपर बांटा गया था।

CJI ने कहा- आरोपियों के बयान अलग-अलग हैं। अगर पेपर लीक (4 मई) की रात को हुआ है, तो जाहिर है कि लीक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रूम वॉल्ट से पहले हुआ था। सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा के साथ संजय हेगड़े, मैथ्यूज नेदुम्परा याचिकाकताओं की ओर से, जबकि सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता NTA और केन्द्र की ओर से पक्ष रख रहे हैं। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहाः NEET-UG 24 परीक्षा में कैंडिडेट्स को एक सवाल के लिए एक सही ऑप्शनचुनना था। इसके लिए दो सही ऑप्शन सुझाए गए। इस पर IIT दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। हम IIT दिल्ली के डायरेक्टर से अनुरोध करते हैं कि 3 एक्सपर्ट्स की टीम बनाएं और इस विषय पर रिपोर्ट दें। एक सही ऑप्शन चुनकर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें। याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ एडवोकेट मुक्ता गुप्ताः इस कैंडिडेट को बहुत ज्यादा पसीना आने की समस्या है लेकिन उसे एग्जाम सेंटर में रूमाल ले जाने की परमिशन नहीं थी। ज्यादा पसीना आने की वजह से इनका एग्जाम बिगड़ गया।

बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा:लोकसभा में सरकार ने 2012 की रिपोर्ट का हवाला देकर मांग खारिज की; लालू बोले- नीतीश इस्तीफा दें

24 न्यूज अपडेट

पटना. विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र से करारा झटका लगा है। सरकार ने साफ किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से 22 जुलाई को संसद में जवाब दिया गया।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जे के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतरराष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।

बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि NDC के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसी को आधार बनाकर केंद्र ने एक बार फिर से बिहार सरकार की इस मांग को

खारिज कर दिया।

हीं, रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। लालू बोले कि नीतीश ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। स्पेशल स्टेट का दर्जा तो हम लेकर रहेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में जदयू ने उठाया था मुद्दा

राजद-जदयू समेत बिहार की कई पार्टियां विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराती रही हैं। वहीं, संसद के मानसून सत्र शुरू होने के पहले 21 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। इसमें भी जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमारी पार्टी की शुरू से मांग रही है। अगर तकनीकी तौर पर इसमें कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिले।

विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों चाहते हैं- मनोज झा

राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों चाहते हैं। बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। इस मांग को कई लोग अवास्तविक बताते हैं। हम केंद्र सरकार की नीतियों में बदलाव चाहते हैं, जो बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र मानता है।

इकोनॉमिक सर्वे- सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी:GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान, हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली. इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने आज यानी, सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया।

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है।

इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी बड़ी बातें

ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स में FY24 में गिरावट आई। सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। अगस्त 2023 में, LPG कीमतों में 200 रुपए/सिलेंडर की कटौती की गई थी। वहीं मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए/लीटर की कटौती की।

एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब मौसम, घटते जलाशयों और फसलों के नुकसान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ा। इससे वित्त वर्ष 24 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.5% हो गई। 2023 में ये 6.6% थी। पीएम-सूर्य घर योजना से 30 गीगावॉट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य सोलर वैल्यू चैन में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना है। पीएम-सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू की गई थी। इंडियन इकोनॉमी को बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉन-फार्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी कई लोगों के पास आवश्यक स्किल का अभाव है। अभी, केवल 51.25% युवा ही रोजगार योग्य है। रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़ते पार्टिसिपेशन को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि इस तरह की स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का भारत जैसे विकासशील देश में कोई स्थान नहीं है। इसमें कहा गया है कि ये पूरी इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकता है। FY26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% या उससे कम होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में भी ये बात बताई थी। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 0.7% कम होकर 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक बताया गया है। वहीं इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल GDP 8.2% की दर से बढ़ी। ये लगातार तीसरा साल है जब GDP 7% से ज्यादा दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024 में GDP ग्रोथ 8.2% रही सरकार ने 31 मई को पूरे साल यानी, वित्त वर्ष 2024 के लिए GDP का प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किया था। FY24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही थी। FY23 में GDP ग्रोथ 7% थी। वहीं RBI ने एक महीने पहले FY25 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया था। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 का महंगाई अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा था।

संपादकीय : गरिमा बनाम गुनाह

संवैधानिक पदों का निर्वाह करने वाले लोगों को आपराधिक मामलों में सुनवाई, सजा आदि से इसलिए संरक्षण प्रदान किया गया है कि इससे उस पद की गरिमा आहत हो सकती है। ऐसे लोगों से भी यह स्वाभाविक अपेक्षा रहती है कि वे उस पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करें। मगर इस तकाजे की कई बार अनदेखी की जाती है। खासकर राज्यपालों के कार्य और व्यवहार को लेकर अनेक मौकों पर अंगुलियां उठी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया और राजभवन के अधिकारियों ने उसे राजभवन में चंधक बनाए रखा। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत आपराधिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। उन पर तब तक कोई मुकदमा नहीं चालाया जा सकता, जब तक वे अपने पद पर हैं। तय पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि अनुच्छेद 361 के खंड दो में राज्यपालों को दी गई छूट में मामले की जांच पर रोक का कोई उल्लेख नहीं है। यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में जांच में देरी पीड़िता को न्याय दिलाने में बाधा है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले के मद्देनजर अनुच्छेद 361 की समीक्षा को राजी हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कर मनमानी लाभ लेने वालों पर नकेल कसी है, इसलिए इस मामले में भी लोगों को उम्मीद चनी है कि संवैधानिक संरक्षण की आड़ में राज्यपालों के अपने पद की गरिमा के प्रतिकूल व्यवहारों पर रोक लगाने का कोई व्यावहारिक रास्ता निकल सकेगा। साथ ही इस सिद्धांत की रक्षा होगी कि कानून की नजर में सभी बराबर है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव के अनेक मौके देखे गए और उनमें से कई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या करते हुए उनकी राजनीतिक सक्रियता पर विराम लगाया, उससे भी सर्वोच्च न्यायालय के ताजा कदम पर सबकी नजर रहेगी। यों राज्यपालों की नियुक्तियों को लेकर ही लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। सक्रिय राजनीति में लंबा समय बिता चुके लोगों को राज्यपाल पद की जम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वे राजभवन में रहते हुए भी अपने दल और केंद्र सरकार की इच्छाओं के अनुरूप काम करते देखे जाते हैं। यही वजह है कि जहां उन्हें राज्य की चुनी हुई सरकार के साथ तालमेल बिठा कर फैसले करने चाहिए, वे नाहक उसके काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लंबे समय से यही देखा जा रहा है। इसी आधार पर राज्यपाल शुरू में अपने ऊपर लगे आरोप को राज्य सरकार की साजिश कह कर खारिज करने का प्रयास करते रहे। मगर मामला इतना हल्का है नहीं। किसी राज्यपाल पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप उस पद की गरिमा को चोट पहुंचाने जैसा है। ऐसे मामलों की सच्चाई तो किसी भी हाल में उजागर होनी चाहिए। उसकी जांच को केवल इसलिए नहीं रोक दिया जाना चाहिए कि राज्यपाल को आपराधिक मामलों में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन अगर राज्यपाल के अधिकारों को ऊपर रखा जाएगा, तो आरोप लगाने वाली महिला के न्याय के अधिकार की रक्षा कैसे हो पाएगी। इन्हीं सब सवालों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल को मिले संरक्षण की समीक्षा करेगा। स्वाभाविक अपेक्षा है कि 'कानून की नजर में सब बराबर हैं' का सिद्धांत सर्वोपरि माना जाएगा।

आंदोलन और हिंसा

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक रुख अख्तियार कर लेने से वहां की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वहां के युवा न तो पुलिस-प्रशासन की बात सुनने को तैयार हैं और न प्रधानमंत्री शेख हसीना के अनुरोध और दलील का उन पर कोई असर हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा से अब तक सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा और उग्र प्रदर्शनकारियों को 'देखते ही गोली मारने' के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारत, नेपाल और भूटान समेत अन्य देशों के लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुतबिक, बांग्लादेश में करीब पंद्रह हजार भारतीयों के होने का अनुमान है। इनमें लगभग साढ़े आठ हजार विद्यार्थी हैं। अब तक एक हजार से अधिक विद्यार्थियों समेत 4,500 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से बाकी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच, बांग्लादेश- भारत सीमा पर सतर्कता बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। दरअसल, बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन पर उतरे युवा उस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में तीस फीसद तक आरक्षण का प्रावधान है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आरक्षण की इस व्यवस्था के जरिए प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने मुक्ति संग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि युद्ध में भाग लेने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, भले वे किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हों। बांग्लादेश सरकार और प्रदर्शनकारियों की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या अपनी मांगों को मनवाने की हिंसा ही एकमात्र उपाय है? जहां प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, वहीं सरकार को चाहिए कि सड़कों पर उतरे युवाओं को किसी तरह भरोसे में ले, ताकि पहले हिंसा थमे।

निपाह वायरस को लेकर राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज को भेजा अलर्ट, केरल से आने वाले यात्रियों के लिए भी टूरिस्ट अलर्ट

24 न्यूज अपडेट

चित्तौड़गढ़। 29 जुलाई को चित्तौड़ 24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। निपाह वायरस के केरल में डिटेक्ट होने और एक मरीज की मौत के बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, सीएमएचओ, पीएमओ को अलर्ट किया है। इसके साथ ही केरल से ट्रैवल करके आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के अनुसार बताया गया है कि हॉस्पिटल में आने वाले संदिग्ध मरीजों को डिटेक्ट करने और उनकी सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस केस में मरीजों को तेज सिरदर्द और बुखार की शिकायत आती है। समय के साथ इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इसमें ब्रेन इन्फेक्शन या इंसेफलाइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है। निपाह वायरस मूल रूप से चमगादड़ों के सपंर्क में आने से फैलता है। उनके खाए फलों को खाने से इसके सबसे ज्यादा फैलने की आशंका रहती है। खास बात ये है कि यह रोग जानवरों से नहीं, बल्कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है अब तक। विभाग ने विशेष रूप से केरल से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए है। इसके लिए होटल संचालकों को भी अलर्ट करने के लिए कहा है, ताकि उनके यहां केरल से आ रहे टूरिस्ट पर निगरानी रखी जा सके।

जयपुर से केकड़ी विधायक के लिए जूते लेकर पहुंचे सीएम:231 दिन बिना जूते-चप्पल के रहे; सीएम बोले- गैंगस्टर राजस्थान आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं

24 न्यूज अपडेट

केकड़ी (अजमेर).केकड़ी (अजमेर) विधायक शत्रुघ्न गौतम ने 231 दिन बाद जूते-चप्पल पहने। विधायक के लिए खुद सीएम कार्यक्रम में जयपुर से जूते लेकर पहुंचे। दरअसल, सोमवार को केकड़ी के ही कृषि मंडी प्रांगण में 2024-25 के लिए जिले के लिए दिए बजट को लेकर धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे।

सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा- पहले गैंगस्टर राजस्थान में शरण लेते थे। अब कोई गैंगस्टर राजस्थान आएगा तो वापस नहीं जाएगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम के दिन छोड़ दिए थे जूते-चप्पल पहनने

विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि 'मैंने विधानसभा चुनावों में नामांकन के समय घोषणा की थी कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर विधानसभा भेजती है तो मैं केकडी-देवली-नसीराबाद सड़क के फोर लेन होने की घोषणा तक चप्पल-जूते नहीं पहनूंगा। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैने चुनाव परिणाम के दिन (3 दिसम्बर 2023) ही चप्पल-जूतों का त्याग कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य सड़क नहीं है। यह सड़क बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, ब्यावर, नागौर और अजमेर के लोगों को अगर कोटा, एमपी और उत्तर प्रदेश जाना होता है तो इस सड़क का उपयोग लोग करते हैं। यह 96 किलोमीटर की सड़क है, इसके करीब 50 किलोमीटर के दायरे में सड़क के दोनों ओर पाइपलाइन बिछी हुई है'। विधायक ने बताया कि- जनता के किए वादे के अनुसार मैंने 231 दिनों तक न जूते पहने और न चप्पल। जहां भी जाता नंगे पैर जाता। अब जब वादा पूरा किया तो सीएम की मौजूदगी में मैंने जूते-चप्पल पहने।

गंगु कुंड परिसर में 26 लाख रूपये के निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर 22 जुलाई / वार्ड 46 में गंगा के चौथे पाये गंगु कुंड परिसर मे 26 लाख रूपये की लागत से लगने वाली इन्टरलॉकिंग टाईल्स निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को निर्माण समिति के अध्यक्ष आशीष कोठारी, वार्ड पार्षद एवं गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी, पूर्व बार अध्यक्ष रामकृपा शर्मा, मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र मारू, महामंत्री महेश भावसार ने पंडित दुर्गेश पालीवाल के द्वारा विधि विधान के साथ शुरू हुआ। यह कार्य दो माह में पूरा हो जायेगा। इस अवसर पर मनोहर चौधरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षो में वार्ड में 08 करोड़ रू. से अधिक के कार्य कराये गये है। इस कार्य से गंगु कुंड परिसर में आने वाले भक्तों एवं पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर प्रेम सुथार, लोकेश जोशी, शिव शंकर नागदा, धनराज, गोपाल, जेईएन आदित्य आमेटा, एईएन प्रवीण बंसल, सुरेश सालवी, नरेश औदिच्य, यशवंत चौधरी, सुरेश रावत, केके कुमावत, नवीन पालीवाल, चिराग वसीटा, कुलीन नागदा, भंवर लाल बंजारा, सुरेश चपलोत, अयुब छीपा, उदय लाल सेन, गणेश पालीवाल सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एमडीएस स्कूल में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुरं एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की न्यासी श्रीमती पुष्पा सोमानी ने माँ सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गण का मंगल तिलक एवं उपरणा द्वारा स्वागत किया गया। कक्षा 6 की छात्राओ द्वारा गुरु वंदना पर नृत्य की प्रस्तुति द्वारा सभी का मनमोह लिया गया। कक्षा 8वीं की छात्रा अविशा दशहारदा ने अपने प्रभावशाली भाषण में गुरु की महिमा पर अनमोल विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय के कक्षा 4,5 व 6 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए समूह गान की मधुर आवाज ने सबको भावविभोर कर दिया। कक्षा 9वीं के छात्रों ने संस्कृत के ज्ञानवर्धक दोहे गुरू की महिमा का बखान करते हुए प्रस्तुत किए। एमडीएस के निदेशक डॉ. शैलेन्द्र सोमानी ने सभी विद्यार्थियों को अपने जीवन में गुरु की भूमिका का महत्व समझने और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि गुरु की शिक्षा और मार्गदर्शन से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं एवं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम ने विद्यालय में गुरु-शिष्य परंपरा को और भी मजबूत किया तथा विद्यार्थियों में गुरु के प्रति आदर और सम्मान का भाव जागृत किया।

डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड के AC में शॉर्ट सर्किट, सभी 8 बच्चे सुरक्षित

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट.डूंगरपुर। मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू वार्ड के एसी में शॉर्ट सर्किट से आज आग लग गईं। चिंगारी के साथ धुंआ निकलने लगा जिस पर अफरा तफरी मची। फायर अलार्म बजने लगा। स्टाफ ने वार्ड में भर्ती बच्चों व परिजनों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में भी सालभर पहले आग की घटना हुई थी। जिसमें भी कई बच्चे बाल-बाल बच गए थे।

इधर आज की घटना में अस्पताल स्टाफ ने समय रहते वार्ड में भर्ती सभी 8 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में सोमवार को अचानक एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग लग गई। एसी से धुंआ निकलने के साथ ही आग लगने पर फायर अलार्म बज उठा। जिसके बाद वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। फायर अलार्म की सूचना पर अस्पताल का स्टाफ मौके पर पहुंचा और वार्ड में भर्ती सभी 8 बच्चों व उनके परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्टाफ ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिसके चलते ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।

अनियमितताएं पाए जाने पर 15 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित

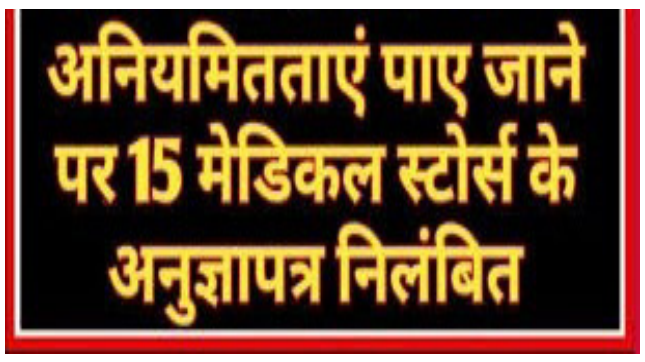

24 न्यूज अपडेट

बीकानेर, 22 जुलाई। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 15 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलम्बित किए गए हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि हेड पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित दुर्गा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 2 दिनों के लिए, पूनरासर स्थित भारत मेडिकोज एंड जनरल स्टोर, छत्तरगढ़ स्थित भावना मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 3 दिनों के लिए, हॉस्पिटल रोड खाजूवाला स्थित एकता मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 4 दिनों के लिए, चौपड़ा बाड़ी गंगाशहर स्थित श्री विद्या मेडिकोज, आरडी 682 स्थित बीकानेर मेडिकल स्टोर, बदरासर स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर, बिंजरवाली स्थित दुर्गा मेडिकोज, सांखला फांटा कोलायत स्थित आयुष मेडिकल एंड जनरल स्टोर, गणगौर स्कूल के पास बंगलानगर स्थित दिव्यांशु मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बड़ेरण स्थित गणेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 10 दिनों के लिए, पुराना बस स्टैंड नोखा रोड बीकानेर स्थित श्री लक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 15 दिनों के लिए, जनता प्याऊ स्थित श्री राजेंद्र मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आरएसी बटालियन के सामने बीछवाल स्थिति बिजारणिया ब्रदर्स मेडिकल एजेंसी तथा अमरसिंहपुरा स्थित दानिश मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 20 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

24 न्यूज अपडेट

बीकानेर, 22 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो, छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदक पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति एवं भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयसेवी संस्था या ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। संयुक्त निदेशक पंवार ने बताया कि कक्षा 1 से 4 तक पांच सौ रुपए प्रतिमाह एवं कक्षा 5 से 8 तक छह सौ रुपए का प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देय है। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति के आवेदन भारत भारत सरकार द्वारा नेशनल ई-स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत संचालित पोर्टल www.scholarships.gov.in पर आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक को आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, बैंक पास बुक प्रति एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

हर नागरिक की आन, बान, शान है तिरंगा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर 22 जुलाई / राष्ट्रीय झण्डा दिवस पर जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि देश के हर नागरिक की आन, बान, शान है तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज आम जन की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। भारतीय संविधान की ओर से 22 जुलाई, 1947 को एक बैठक के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। पिंगली वैंकया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। विद्यापीठ के मुख्य द्वार पर 151 फीट का तिरंगा लगाया गया है जिससे आने जाने वाले को इससे प्रेरणा मिलती है।

सुप्रीम कोर्ट में सीकर के NEET रिजल्ट पर उठा सवाल:देशभर में एक सेंटर से सिलेक्शन 0.6 फीसदी, अकेले सीकर में 25% गलत पेपर तक बांटा

24 न्यूज अपडेट

सीकर\कोटा. NEET विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई खत्म हुई। सुनवाई के दौरान राजस्थान के नीट सेंटर्स पर भी सवाल उठे। सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया कि देश में औसत एक सेंटर पर नीट के लिए सिलेक्शन 0.6 फीसदी है, लेकिन अकेले सीकर में यह करीब 25 फीसदी हो गया है।

NEET में 500 से ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले

छात्र जिन टॉप 100 परीक्षा केंद्रों के हैं, उनमें से 71 राजस्थान के है। इन 71 में से अकेले सीकर के 46 सेंटर है। वहीं जयपुर के 16, कोटा के 8 और बीकानेर का 1 सेंटर शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा के साथ संजय हेगड़े, मैथ्यूज नेदुम्परा ने याचिकाकताओं और सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने NTA और केंद्र की ओर से पक्ष रखा। राजस्थान से भी जुड़ा NEET विवाद इस बार NEET विवादों में रहा है। सेंटर पर पेपर लेट मिलने से लेकर ग्रेस मार्क्स पर स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए थे। राजस्थान में भी कई जिलों के सेंटरों पर स्टूडेंट्स को देरी से पेपर दिया गया था। वहीं सवाई माधोपुर में पेपर के दिन हंगामा हुआ था, जिस पर भी आज कोर्ट में सवाल उठाया गया। हाल ही में NEET पेपर लीक मामले में CBI ने भरतपुर (राजस्थान) के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के दो स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है।

कोर्ट में सीकर सेंटर से हुए सिलेक्शन पर उठा सवाल

1- सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया- सीकर में 700 से ऊपर 8 कैंडिडेट्स, 650 से ऊपर 69 कैंडिडेट्स, 600 से ऊपर 115 कैंडिडेट्स, 550 से ऊपर स्कोर करने वाले 241 कैंडिडेट्स हैं। सिटी कोऑर्डिनेटर ही इन स्कूलों के ओनर हैं। ये प्राइवेट स्कूल है। इनविजिलेटर इन स्कूलों के कर्मचारी है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये टीचर्स कोटा और सीकर के कोचिंग सेंटरों से मिले हुए हैं।

2- सीकर और महेंद्रगढ़ जैसी जगहों पर कंसंट्रेशन हो रहा है, वहां ओएमआर शीट में हेराफेरी हो रही है। निजी इनविजिलेटर्स के पास 5:20 बजे बाद भी ओ एमआर शीट आई है। उन्हें शीट भरने और 3 घंटे के बाद सिटी सेंटर में जमा करने से कौन रोक सकता है।

3- नेशनल लेवल पर 1000 में से 6 लोगों ने एवरेज 650 अंक से ऊपर स्कोर किया है। वहीं सीकर में हर चार में से एक कैंडिडेट ने 650 से ज्यादा स्कोर किया है।

4- डाटा एनालिसिस करने पर पता चलता है कि कुछ सेंटर अच्छा काम कर रहे हैं, कैंडिडेट्स नहीं। देश के टॉप सेंटर्स की गिनती करें तो वहां 50 में से 38 केंद्र केवल सीकर में है।

5- जनरल कैटेगरी में 640 से 650 अंक पर सरकारी कॉलेज मिलना संभव होता है। इस आधार पर माना जा रहा है कि सीकर में सक्सेस रेट प्रतिशत ज्यादा रहा है।

650 अंक पाने वाले 2037 परीक्षार्थी अकेले सीकर से

नीट के 23.22 लाख स्टूडेंट्स में से 30,204 को 650 अंक मिले हैं। इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 30,000 सीटों पर मौका मिलेगा। इन पर अकेले सीकर के सेंटर्स के 2037 परीक्षार्थी दावेदार होंगे।

ऋषि गालव और तुलसीदास की तपोभूमि गलता पीठ के महंत की नियुक्ति कोर्ट ने रद्द किया, अदालत ने कहा-गलता पीठ के अवधेशाचार्य स्वयंभू महंत बने हुए हैं, सरकार को पीठ टेकओवर करने के निर्देश

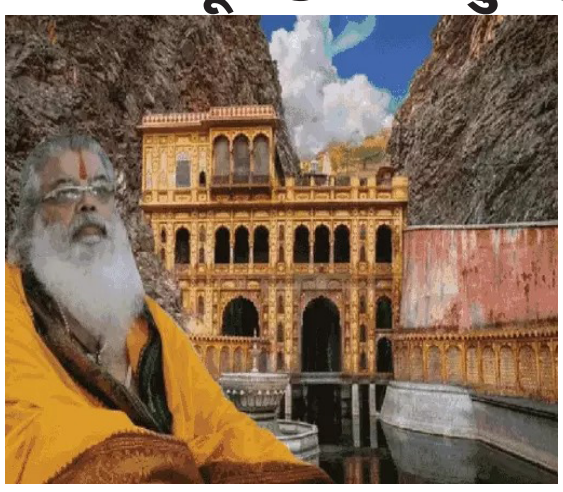

24 न्यूज अपडेट

जयपुर. जयपुर के गोनेर रोड पर शनिवार दोपहर 24 न्यूज अपडेट, स्टेट डेस्क। जयपुर के प्रसिद्ध गलता पीठ तीर्थ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को आज राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने अवधेशाचार्य व अन्य की अपीलों को निस्तारित करते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने पीठ को टेकओवर करके सन् 1943 की स्थिति बहाल करने के सरकार से निर्देश दिए हैं। गलता पीठ की अब तक बेची गई सभी संपत्तियों के बेचान को भी निरस्त कर दिया है। महंत अवधेशाचार्य, उनकी मां गायत्री देवी और अन्य ने देवस्थान आयुक्त के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। अदालत ने 22 फरवरी को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा- गलता पीठ के अवधेशाचार्य स्वयंभू महंत बने हुए हैं। उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है। जयपुर स्टेट ने उनके पिता रामोदाचार्य को महंत नियुक्ति किया था। उनके बाद महंत नियुक्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। इसलिए अवधेशाचार्य की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है। अधिवक्ता उमाशंकर शर्मा ने बताया- साल 1939 तक गलता पीठ में कोई महंत नहीं था। उसके बाद जयपुर स्टेट ने प्रस्ताव पास करते हुए महंत के लिए आवेदन मांगे। उसके बाद रामोदाचार्य को गलता पीठ का महंत नियुक्त किया गया था। लेकिन उन्होंने पीठ के नियम के विरूद्ध 1963 में राजस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड करवा लिया। बाद में ट्रस्ट के विधान में परिवर्तन करके उसे वंश परंपरा के तहत रजिस्टर्ड करा लिया। अपने वंशजो में गलता पीठ की प्रॉपर्टी को बांट दिया। बता दें कि गलत पीठ की प्रॉपर्टी व जयपुर, डीग, भरतपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने देवस्थान विभाग के अस्सिटेंट कमिश्नर को यह मामला सुनने के आदेश दिए। देवस्थान कमिश्नर ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इसके खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे। गलता पीठ का विकास राम मंदिर और महाकाल मंदिर की तर्ज पर करने के लिए कहा गया। अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छापा ने बताया हाईकोर्ट ने सरकार को गलता पीठ व उससे जुड़ी संपत्तियों को टेकओवर करने के निर्देश दिए हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच गलताजी सतयुग के ऋषि गालव की तपोभूमि है। जहां उन्होंने करीब 60 हजार साल तक तपस्या की थी। यहीं पर करीब 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस का अयोध्या कांड लिखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने रोका सरकार का फैसला, कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट जरूरी नहीं, पूछा यह बताएं कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के छळव् ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वे किस तरह का खाना अर्थात शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं। लेकिन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले के करीब 240 किमी एरिया में कांवड़ मार्ग पड़ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले, जहां से कांवड़िए खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था, ताकि कांवड़ियों में कोई कन्फ्यूजन न रहे और कानून व्यवस्था में बाधा न आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। इधर, यूपी सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक, कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसके बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था। उज्जैन में नगर निगम यह आदेश एक साल पहले ही दे चुका था।

श्रीनाथ मंदिर में 352 साल पुराना परीक्षण, अच्छी बारिश का दावा

27 अनाज-सामग्री के तौल से लगाया पूर्वानुमान; फसल अच्छी होगी, चारा कम

24 न्यूज अपडेट

नाथद्वारा (राजसमंद). नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ मंदिर में सोमवार को 352 साल पुरानी आषाढ़ी तौल परंपरा निभाई गई। इस परंपरा से सालभर में होने वाले बिजनेस, फसल और बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया। इस परंपरा के आधार पर दावा किया गया कि इस बार प्रदेश में अच्छी फसल होगी। लेकिन, पशुओं के लिए चारा कम होगा। वहीं, सावन-भादो में अच्छी बारिश होने का दावा किया गया। जबकि हवा को लेकर दावा किया गया कि इस बार पश्चिमी दिशा की हवा का असर ज्यादा रहेगा। मंदिर के पुरोहित डॉ. परेश नागर पंड्या ने बताया- खर्च भंडार में रविवार शाम 27 तरह के अनाज और सामग्रियों को तौल कर अनाज भंडार में रखा गया था। आज सुबह इसे फिर से तौला गया। दोनों तौल के दौरान सामग्री का वजन कम या ज्यादा होने के आधार पर सालभर का पूर्वानुमान निकाला गया है। आषाढ़ी तौल में इस बार वजन बढ़ा है। 352 साल पुरानी है आषाढ़ी तौल परंपरा नाथद्वारा में हर साल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को श्रीनाथ मंदिर के खर्च भंडार में यह परंपरा निभाई जा रही है। इसका कोई लिखित इतिहास

नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि श्रीनाथ जी 352 साल पहले ब्रज से मेवाड़ में पधारे थे। वे सिहाड़ गांव में रुके थे। विक्रम संवत 1728 (20 फरवरी 1672 ईस्वी) को श्रीनाथ जी नाथद्वारा में पाट पर विराजे थे। यह परंपरा तभी से शुरू हुई थी।

इस परंपरा के मुताबिक 22 प्रकार के धान, काली व लाल मिट्टी, नमक, गुड़ और चारा सहित कुल 27 प्रकार की सामग्री तौली जाती हैं। इस तौल से अगले साल होने वाली पैदावार, व्यापार और मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसे आषाढ़ी तौलना कहते हैं। इस बार 24 सामग्रियों का वजन बढ़ा रविवार को पूर्णिमा पर तौल कर रखे गए धान और सामग्रियों को सोमवार सुबह भगवान श्रीनाथ के ग्वाल दर्शन के वक्त फिर से तौला गया। रात के तौल और सुबह के तौल में अंतर के आधार पर पूर्वानुमान लगाया गया। डॉ. परेश नागर ने बताया- कपास और लाल गारा का वजन बराबर आया। इनका उत्पादन आगामी साल में समान रहेगा। घास के तौल में कमी हुई है। वहीं, 24 तरह की सामग्री के वजन में वृद्धि हुई है। इनमें हरा मूंग, सफेद मक्की, पीली मक्की, बाजरा, ज्वार, साल सफेद, साल लाल, चंवला छोटा, चंवला मोटा, तिल्ली सफेद, तिल्ली काली, उड़द, मोठ, ग्वार, जौ, गेहूं काठा, गेहूं चन्द्रेसी, चना पीला, चना लाल, सरसों पीली, सरसों लाल, गुड़, नमक और काला गारा में बढ़ोतरी के संकेत हैं। यहां काला गारा (काली मिट्टी) को मनुष्य और लाल गारा (लाल मिट्टी) को पशु का प्रतीक माना जाता है।

अनाज की पैदावार अधिक होगी

मुख्य पंड्या डॉ. परेश नागर ने कहा- इस साल अनाज की पैदावार ज्यादा होगी। गर्जना के साथ सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। पूर्वानुमान की भाषा के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार आषाढ़ में पांच आना, श्रावण में चार आना, भाद्रपद में तीन आना और आसोज में चार आना (प्रतिशत) बारिश होगी। यानी इस बार बारिश सामान्य से ज्यादा होगी। साथ ही वायु की दिशा पश्चिम रहने से तेज हवा और गर्जना के साथ बारिश का दौर चलेगा।

पेपर लीक माफिया भांभू के घर पर चला बुलडोजर

2 प्लॉटों पर कर रखा था अवैध निर्माण, SI भर्ती पेपर लीक मामले में SOG ने किया था गिरफ्तार

24 न्यूज अपडेट

चूरू. राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से गिरफ्तार आरोपी विवेक भांभू के घर पर सोमवार को नगर परिषद की टीम ने बुलडोजर चला दिया। आरोपी विवेक भांभू ने चूरू की पूनिया कॉलोनी में दो प्लॉटों पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करा रखा था। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आरोपी विवेक भांभू एसआई भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड यूनिक भांभू का छोटा भाई है। इसका एसआई भर्ती परीक्षा में चयन हो गया था। नगर परिषद के सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजीनियर) रवि कुमार राघव के नेतृत्व में सोमवार दोपहर नगर परिषद की जेसीबी और ट्रैक्टर पूनिया कॉलोनी की गली नंबर 11 में पहुंचे। टीम एसआई पेपरलीक मामले में गिरफ्तार आरोपी विवेक भांभू के प्लॉट नंबर 114 और 115 पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इन प्लॉटों बिना परिषद की परमिशन के अवैध निर्माण करवाया हुआ था, जिसको जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कर दिया। प्लाटों में एक कमरा, एक लेट बाथ, दो टीन शेड के बने ढारे और प्लॉट के चारों तरफ चारदीवारी बनी हुई थी। डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया ने बताया- एसआई पेपरलीक मामले में गिरफ्तार आरोपी विवेव भांभू का घर है। जिसको नगर परिषद के आदेश से जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यह घर नगर परिषद की बाउंड्री में बना हुआ है और अवैध रूप से बिना परमिशन के बना है। इसलिए इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।

पथराव में मालपुरा ASP समेत 12 पुलिसकर्मी घायल:सिन्धोलिया में खनन बंद करवाने पहुंचे ग्रामीण, पुलिस के समझाने पर हुए उग्र

24 न्यूज अपडेट

टोंक. खान में पत्थर खनन विवाद को लेकर समझाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे मालपुरा ASP समेत दस-बारह पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, छह पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की जीप के शीशे फोड़ दिए। ग्रामीणों का गुस्सा देख पुलिस पीछे हट गई। पुलिस की और फोर्स आने पर करीब 12 बजे ग्रामीण वहां से चले गए। घायल पुलिसकर्मियों का घटनास्थल के पास के गांव में निजी डॉक्टर से प्राथमिक उपचार कराया गया है। मामला सोमवार सुबह 11 बजे टोंक जिले में मालपुरा उपखंड क्षेत्र के लांबाहरिसिंह सिन्धोलिया गांव का है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने पशु नहीं चरा पा रहे हैं। स्टे के बावजूद खनन शुरू हो गया है। जबकि लीज धारक का कहना है कि स्टे हट गया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए SP संजीव नैन ने गांव के आसपास अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया है। मालपुरा ASP रामकुमार कस्वां ने बताया कि मालपुरा से करीब बारह किमी दूर सिंधोलिया गांव है। उसमें पहाड़ी क्षेत्र में खाते की जमीन में 2021 में खान लीज हुई थी। गांव के कई ग्रामीण इस खान से खनन के विरोध में थे। फिर इस खान में खनन पर स्टे ले लिया। ग्रामीण चाहते हैं कि इस क्षेत्र में खनन नहीं हो ताकि उनके मवेशी चर सकें। करीब दस दिन पहले स्टे हट गया। इसके चलते लीज धारक ने गत दिनों खनन शुरू करवा दिया। लीजधारक डिग्गी के रामप्रताप सिंह ने विकास चौधरी को कॉन्ट्रेक्ट बेस पर दे खान दे रखी है। इससे नाराज सिंधोलियों के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर आज सुबह करीब 11 बज खनन कार्य बंद करवाने चले गए। ग्रामीणों ने खान में तोड़फोड़ कर दी। इसकी सूचना मिलने के बाद लांबाहरिसिंह पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पथराव की सूचना मिलने पर मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने बिना बात करे ही फिर पथराव कर दिया। इससे मालपुरा ASP रामकुमार कस्वां, उनका गनमैन समेत दस-बारह पुलिसकर्मी घायल हो गए।

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ

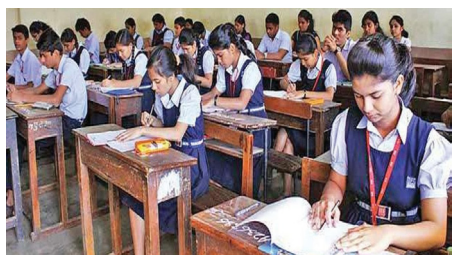

24न्यूजअपडेट

डूंगरपुर, 22 जुलाई। जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा डूंगरपुर की कक्षा-6 में सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 15 जुलाई से प्रारम्भ हो चुकी हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा के प्राचार्य ने बताया कि जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन निःशुल्क कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण हैं। आवेदन वर्तमान सत्र 2025-26 में डूंगरपुर जिले में प्रवेश चाहता है तो वह जिले का निवासी हो तथा उसी जिले के किसी भी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक की जन्म तिथि 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 (दोनों तिथियों भी शामिल) के बीच होनी चाहिए। वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो (पिछले सेशन में कक्षा 5 करने वाले या वर्तमान में कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन योग्य नहीं हैं) पिछले वर्ष नवोदय की प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी (रिपीटर) भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। कुल चयन में से 75 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में लिए जाएंगे। कुल सीट में से कम से कम 1ध्3 सीटों पर छात्राओं का चयन होगा। अधिक जानकारी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा डूंगरपुर के हेल्प डेस्क सूर्यकांत काले मोबाइल नंबर 9527054334 एवं पूनम गर्ग 9039288771 से सम्पर्क कर सकते हैं।

डूंगरपुर में संभागीय आयुक्त ने सीज करवाया फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. डूंगरपुर। डूंगरपुर-बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन सोमवार को डूंगरपुर पहुंचे और रेती स्टैंड पर स्थित एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट का औचक निरीक्षण किया। बांसवाड़ा में मिला फर्जी इंस्टीट्यूट डूंगरपुर में चालू मिलने पर संभागीय आयुक्त ने सेंटर को सील कर एफआईआर करवाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने सेंटर को हाथोंहाथ सील कर दिया। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन राजस्थान इंस्टीट्यूट नर्सिंग कंसल्टेंट गए व स्टाफ के बारे में पूछा। वहां पर दो का स्टाफ मिला। कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों से जानकारी ली तो वे भी कोई सही जवाब नहीं दे सके। इसकी मुख्य ब्रांच बांसवाड़ा में चल रही है। जांच में फर्जी मिलने पर संस्थान को हाथों हाथ बंद कर करवाया गया। संभागीय आयुक्त ने सीएमएचओ को मौके पर बुलाकर संस्थान को तत्काल सील करने के साथ ही एफआईआर करवाने के निर्देश दिए। इसे बाद सीएमएचओ ने सेंटर को सील कर दिया तो दोनों कर्मचारियों को डिटेन कर कोतवाली थाने ले गए। बडा सवाल यह उठता है कि अब तक सीएमएचओ क्या कर रहे थे। उन्होनें इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की।

24 न्यूज अपटेड
देश-दुनिया राज्यों एवं स्थानीय खबरें को देखने के लिए
हिन्दी समाचार पत्र एवं न्यूज़ चैनल
ताजा खबरें देखने के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें
YouTube
24 NEWS UPDATE
हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें
लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।